



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

2 भाद्र 1940 (श10)

(सं० पटना 787) पटना, शुक्रवार, 24 अगस्त 2018

सं० 06/पणन (सं०)—53/2017—2639
सहकारिता विभाग

संकल्प

7 अगस्त 2018

विषय : कृषि रोड मैप (2017-22) के अंतर्गत पैक्सों/व्यापारमंडलों में वित्तीय वर्ष 2018-22 तक कुल 8 लाख मे०टन भंडारण क्षमता के सृजन हेतु 200 मे०टन, 500 मे०टन या 1000 मे०टन प्रति इकाई क्षमता के गोदाम निर्माण के लिए उक्त समितियों को 50% अनुदान तथा 50% चक्रिय पूँजी के रूप में वर्षवार कुल 560 करोड़ (पाँच सौ साठ करोड़) रुपये के विरुद्ध योजना प्रारंभ करने हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए 175 करोड़ रु० का व्यय सहकारी समितियों को राज्य योजना से प्राप्त उद्व्यय एवं बजट उपबंध की राशि से करने की स्वीकृति के संबंध में।

राज्य में विभिन्न व्यवसायिक क्षेत्रों में पैक्सों एवं व्यापारमंडलों की बढ़ती भूमिका यथा धान/गेहूँ अधिप्राप्ति, जन वितरण संबंधी कार्य एवं कृषि में प्रयोग होनेवाले खाद्यानों की आपूर्ति को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा पैक्स/व्यापारमंडल सहकारी समितियों के आधारभूत संरचनाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से कृषि रोड मैप (2017-22) के अंतर्गत पैक्सों/व्यापारमंडलों में वित्तीय वर्ष 2018-22 के लिए वर्ष 2018-19 में 2.5 लाख मे०टन भंडारण क्षमता हेतु 175 करोड़, वर्ष 2019-20 में 2.5 लाख मे०टन भंडारण क्षमता हेतु 175 करोड़, वर्ष 2020-21 में 1.5 लाख मे०टन भंडारण क्षमता हेतु 105 करोड़ एवं वर्ष 2021-22 में 1.5 लाख मे०टन भंडारण क्षमता हेतु 105 करोड़ रुपये अर्थात् 2018-22 तक कुल 8 लाख मे०टन भंडारण क्षमता के सृजन हेतु 200 मे०टन, 500 मे०टन या 1000 मे०टन प्रति इकाई क्षमता के गोदाम निर्माण के लिए उक्त समितियों को 50% अनुदान तथा 50% चक्रिय पूँजी के रूप में वर्षवार उपलब्ध कराने हेतु कुल 560 करोड़ (पाँच सौ साठ करोड़) रुपये व्यय की योजना का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

2. योजना का भौतिक आकार एवं कार्यान्वयन समय-सीमा:— वित्तीय वर्ष 2018-22 में पैक्सों/व्यापारमंडलों में 8 लाख मे०टन भंडारण क्षमता सृजन करने हेतु 200 मे०टन, 500 मे०टन या 1000 मे०टन क्षमता का गोदाम निर्माण किया जाना है। गोदाम निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2018-22 में कुल 560 करोड़ रुपये का व्यय कृषि रोड मैप के अंतर्गत अनुमानित है। प्राक्कलन में संशोधन के अनुरूप प्राक्कलित राशि के अंतर्गत गोदाम निर्माण में परिवर्तन हो सकता है।

3. वित्तीय स्रोत:—पैक्सों/व्यापारमंडलों को वर्ष 2018-22 में गोदाम निर्माण हेतु आवश्यक निधि 560 करोड़ रुपये राज्य योजनांतर्गत प्राप्त राशि से पैक्सों/व्यापारमंडलों को सहकारी बैंक के माध्यम से 50% अनुदान तथा 50% चक्रिय पूँजी के रूप में उपलब्ध कराया जाएगा।

उपर्युक्त योजना अन्तर्गत राज्य योजना में वित्तीय वर्ष 2018-22 में “गोदाम निर्माण हेतु सहकारी समितियों को अनुदान” मद में वर्षवार उपलब्ध उद्ध्यय एवं उपबंध के विरुद्ध व्यय किया जायेगा तथा अतिरिक्त राशि का उद्ध्यय एवं उपबंध प्राप्त करने हेतु कार्रवाई की जाएगी।

4. चक्रीय पूँजी की वापसी:—राज्य योजना द्वारा पैक्सों/व्यापारमंडलों को गोदाम निर्माण हेतु उपलब्ध करायी गयी चक्रीय पूँजी की वापसी, योजना वर्ष के अगले वर्ष से 20 अर्द्धवार्षिक समान किस्तों में 10 वर्ष में की जा सकेगी। उक्त राशि वापसी से बिहार राज्य सहकारी बैंक में एक Revolving Capital का सृजन तथा संधारण किया जायेगा जिसका उपयोग पैक्सों एवं व्यापारमंडलों के आधारभूत संरचनाओं के रख-रखाव/मरम्मत हेतु अलग से योजना तैयार कर इसी प्रकार की चक्रीय पूँजी समितियों को उपलब्ध कराने हेतु किया जा सकेगा।

पैक्सों एवं व्यापारमंडलों को गोदाम निर्माण हेतु उपलब्ध करायी गयी चक्रीय पूँजी का अभिलेख संबंधित जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक तथा जिला सहकारिता पदाधिकारी के कार्यालय में संधारित होगा जिसमें दी गई चक्रीय पूँजी का ब्यौरा, किस्त वापसी की राशि एवं तिथि के साथ-साथ समितियों द्वारा राशि वापसी का भी ब्यौरा होगा। बैंक के स्तर से राशि वापसी का पूरा ब्यौरा अंकित करते हुए वापसी तिथि के एक माह पूर्व मांग पत्र समितियों को प्राप्त कराया जायेगा। राशि वापसी में चूक की स्थिति में लोक मांग वसूली अधिनियम के तहत कार्रवाई की जायेगी।

5. भूमि की व्यवस्था:—पैक्सों में होने वाले गोदाम निर्माण कार्य हेतु भूमि पैक्सों द्वारा ही उपलब्ध कराया जाना है और भूमि का निबंधन/लीज पैक्सों के पक्ष में किया जाना अनिवार्य होगा। इस क्रम में पैक्सों के पास पूर्व से उपलब्ध जमीन अथवा सरकार द्वारा उपलब्ध कराया गया भूमि अथवा दान के माध्यम से अथवा पैक्सों के द्वारा अपने संसाधन से खरीदी अथवा लीज पर ली गई जमीन का उपयोग हो सकेगा। व्यापारमंडल में कराये जाने वाले निर्माण कार्य हेतु भूमि संबंधित प्रखण्ड कार्यालय परिसर स्थित व्यापारमंडल हेतु कर्णांकित भूमि पर कराया जाएगा। जिन प्रखण्डों में व्यापारमंडल के लिए भूमि कर्णांकित नहीं है वहाँ सरकारी भूमि उपलब्ध कराने हेतु सक्षम प्राधिकार से अधिग्रहण किया जाएगा। भूमि की व्यवस्था के संबंध में विभागीय दिशा-निर्देश का अनुपालन किया जाएगा।

समितियों का चयन : गोदाम निर्माण हेतु पैक्सों एवं व्यापारमंडलों का चयन जिला स्तर पर प्रमंडलीय संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियों की अध्यक्षता में गठित चयन समिति द्वारा किया जाएगा।

कार्यान्वयन एजेन्सी : पैक्स/व्यापारमंडल में कराये जाने वाले निर्माण कार्य का कार्यान्वयन पैक्स/व्यापारमंडल द्वारा स्वयं या निविदा के माध्यम से किया जायेगा।

तकनीकी पर्यवेक्षण : परियोजना का मॉडल नक्शा तथा प्राक्कलन बिहार राज्य भंडार निगम से तैयार कराते हुए भवन निर्माण विभाग से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त की गई है जो लाभान्वित समितियों तथा संबंधित जिला के पदाधिकारियों को उपलब्ध कराया जायेगा परन्तु स्थानीय मानकों के आलोक में संबंधित जिला पदाधिकारी के द्वारा अधिकृत अभियंता के स्तर पर प्रति इकाई लागत की अधिसीमा अन्तर्गत Structural Design तथा प्राक्कल जिला पदाधिकारी के अनुमोदन से संशोधन किया जा सकेगा। उपरोक्त योजनाओं के तहत होने वाले निर्माण कार्यों में तकनीकी पर्यवेक्षण जिला पदाधिकारी द्वारा प्राधिकृत असैनिक अभियंता द्वारा किया जायेगा।

6. अनुश्रवण : जिला स्तर पर निर्माण कार्यों का अनुश्रवण जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति जिसमें जिला सहकारिता पदाधिकारी एवं प्रबंध निदेशक जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक सदस्य होंगे, के द्वारा किया जायेगा। गुणवत्ता के अनुरूप कार्य कराने का दायित्व इस समिति पर होगा। मुख्यालय स्तर पर प्रगति का अनुश्रवण निबंधक, सहयोग समितियों द्वारा किया जायेगा।

7. इस योजना के संबंध में विभागीय स्वीकृति पत्र एवं विभागीय दिशा-निर्देश लागू होगा।

8. मंत्रीपरिषद् की दिनांक 31.07.2018 की बैठक में मद संख्या 05 में निहित प्रस्ताव पर स्वीकृति प्राप्त है।

9. यह संकल्प तत्काल प्रभाव से राज्य में प्रभावी समझा जायेगा।

आदेश : आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में सर्व साधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
सुरेश चौधरी,
सरकार के अपर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 787-571+20-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>